Aravalli conservation, afforestation goals, wildlife protection and environment-policy announcements in Rajasthan.

The grants (Demand No. 45) proposed by the Forest and Environment Department have been passed in the Rajasthan by voice vote and this affirms the state drive in seeking to conserve the Aravalli. The aggregate grant demand of the department totaled by 18,75,26,67,000 and it was passed after discussion in the Assembly. The state government has allocated a sum of 130 crore in the current budget towards plantation, protection works and enhanced maintenance of river source areas emerging out of the Aravalli range. On 5 June 2025, as part of the initiative of the Chief Minister, a special project related to the conservation of the Aravalli was inaugurated, making the Aravallis an integral part of the Rajasthan economy, agriculture and environment.

Primary Outlines and Statistics.

Budget on works connected with Aravalli: 130crore on plantation, protection and river-source maintenance.

Harialo Rajasthan results (past 2 years):

- Target: 10 crore saplings
- Achieved: 18.54 crore saplings

"Ek Ped Maa Ke Naam" plantation:

- 2024–25: Target 3 crore; Achieved 7.34 crore
- 2025–26: Target 1.8 crore; Achieved 8.37 crore

The objective is to transform Rajasthan into a major green and pollution-free state by collaborative efforts of the government, society, and industry.

Forest Department Major Announcements.

- Two Shri Ram Vatika to be established in each district.
- Atal Bihari Vajpayee statue to be planted in Shahpura (Jaipur).
- Juvenile training in nature guiding in Alwar branch of the Rajasthan Forestry and Wildlife Training Institute.
- One District one Species: Seed forests will be set up on individual species that the district has.
- New GIS Centre's at headquarters level on forest and wildlife conservation.
- Statewide orders on management of the damage-causing wild boars on crops.
- One employee of each lower cadre in tiger project areas at state level annually awarded on commendable work.
- 460 motorcycles to use by the field staff and patrol, 24/7 (this financial year).
- Stronger defense: glove pistol in RFO/foresters and 2 SLR rifles/naka (this financial year).
- 202 Bolero/Bolero Camper cars/ Range Officers.

Human-Wildlife Conflict and Rescue Strengthening.

Measures

- The amount has been raised to 10 lakh rupees in case of human death due to wildlife.
- Quick Response Teams formed in Dholpur, Karauli, Sawai Madhopur and Alwar.
- ₹90 lakh per district that will be used in wildlife rescue of a vehicle and necessary equipment to use by the group.

Policy Actions in Environment Department.

- Circular Economy Policy which should be implemented in the state.
- E-waste policy of condemnation to be introduced.
- Reward scheme to reinforce the pollution control schemes and promote self-compliance of industries.
- Jaipur-based State Water and Air Laboratory (RSPCB) to receive pesticide-testing facilities that are of the given modern type.

RASonly

Conclusion

The Assembly ratification enhances the Rajasthan governance roadmap in the areas of forests, wildlife security, and environment management, with much exam-relevant emphasis on budgeting, institutional capacity and the quantifiable plantations results. It associates the conservation of the environment with the restoration of the ecology, the ability to enforce, and citizen-oriented practices such as higher compensation and quicker response to the rescue with the package, in addition to indicating future changes by circular economy and e-waste policies.

MCQs (RAS Prelims Pattern)

Q1. The budget of Rajasthan on the plantation and protection activities in association with the Aravalli range is:

(a) ₹90 crore

(b) ₹130 crore

(c) ₹460 crore

(d) ₹202 crore

Answer: (b)

Explanation: The present budget offers 130 crore in plantation, protection and maintenance of river source areas that are of the originating river sources of Aravallis.

Q2. The plantation performance at the plantation during the previous two years under Harialo Rajasthan was:

(a) 10 crore saplings

(b) 7.34 crore saplings

(c) 18.54 crore saplings

(d) 8.37 crore saplings

Answer: (c)

Explanation: 18.54 crore saplings were planted together with a target of 10 crore saplings.

Q3. What group of districts was provided Rapid Response Teams to provide wildlife rescue and response strengthening?

(a) Alwar, Ajmer, Jodhpur, Bikaner

RASonly

(b) Dholpur, Karauli, Sawai Madhopur, Alwar.

(c) Kota, Udaipur, Sikar, Barmer

(d) Jaipur, Bharatpur, Pali, Chittorgarh

Answer: (b)

Explanation : Dholpur, Karauli, Sawai Madhopur and Alwar developed Rapid Response Teams with the help of district level rescue allocations and equipment.

अरावली संरक्षण, वृक्षारोपण लक्ष्य, वन्यजीव सुरक्षा तथा पर्यावरण-नीति घोषणाएं (राजस्थान)

राजस्थान विधानसभा में वन एवं पर्यावरण विभाग की अनुदान मांगें (मांग संख्या–45) ध्वनिमत से पारित की गईं। यह निर्णय अरावली संरक्षण को लेकर राज्य के अभियान को मजबूती देता है। विभाग की कुल अनुदान मांग **₹18,75,26,67,000** रही, जिसे सदन में चर्चा के बाद पारित किया गया। चालू बजट में अरावली क्षेत्र में **वृक्षारोपण, संरक्षण कार्य तथा अरावली से निकलने वाले नदी-स्रोत क्षेत्रों के बेहतर रखरखाव** के लिए **₹130 करोड़** का प्रावधान किया गया है। **5 जून 2025** को मुख्यमंत्री की पहल के अंतर्गत **अरावली संरक्षण से संबंधित विशेष परियोजना** का शुभारम्भ किया गया, जिससे अरावली को राजस्थान की अर्थव्यवस्था, कृषि और पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण आधार के रूप में रेखांकित किया गया।

प्रमुख बिंदु एवं आंकड़े

- **अरावली से जुड़े कार्यों हेतु बजट:** वृक्षारोपण, संरक्षण तथा नदी-स्रोत रखरखाव के लिए **₹130 करोड़**
- **हरियालो राजस्थान (पिछले 2 वर्ष) परिणाम:**
  - लक्ष्य: **10 करोड़** पौधे
  - उपलब्धि: **18.54 करोड़** पौधे
- **'एक पेड़ मां के नाम' अभियान में वृक्षारोपण:**
  - **2024–25:** लक्ष्य 3 करोड़; उपलब्धि **7.34 करोड़**
  - **2025–26:** लक्ष्य 1.8 करोड़; उपलब्धि **8.37 करोड़**
- उद्देश्य: सरकार, समाज और उद्योग के संयुक्त प्रयास से राजस्थान को प्रमुख **हरित एवं प्रदूषणमुक्त राज्य** बनाना।

वन विभाग की प्रमुख घोषणाएं

- प्रत्येक जिले में **2 श्रीराम वाटिका** विकसित की जाएंगी।

RASonly

- **शाहपुरा (जयपुर)** में भारत रत्न **अटल बिहारी वाजपेयी** की आदमकद प्रतिमा स्थापित की जाएगी।
- **अलवर शाखा** (राजस्थान वानिकी एवं वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान) द्वारा युवाओं को **नेचर गाइड** का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- **'एक जिला–एक प्रजाति'** के तहत जिले के लिए निर्धारित प्रजाति का **बीज वन** स्थापित किया जाएगा।
- वन एवं वन्यजीव संरक्षण हेतु मुख्यालय स्तर पर **नवीन जी.आई.एस. सेंटर** स्थापित किया जाएगा।
- फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले **जंगली सूअरों** के नियंत्रण/निपटारे संबंधी आदेश अब **समूचे प्रदेश में लागू** किए जाएंगे।
- बाघ परियोजना क्षेत्रों में अधीनस्थ सेवा के प्रत्येक संवर्ग के **एक कर्मचारी को प्रतिवर्ष** प्रशंसनीय कार्य पर **राज्य स्तर पर पुरस्कृत** किया जाएगा।
- दुर्गम क्षेत्रों में गश्त व सतत निगरानी के लिए फील्ड स्टाफ को इसी वित्तीय वर्ष में **460 मोटरसाइकिलें** उपलब्ध कराई जाएंगी।
- वन्यजीव सुरक्षा व वन अपराध रोकथाम हेतु **क्षेत्रीय वन अधिकारी/वनपाल** को **ग्लोव पिस्टल** तथा प्रत्येक नाके पर **2 एस.एल.आर. राइफल** इसी वित्तीय वर्ष में दिए जाने की व्यवस्था।
- रेंज अधिकारियों को **202 बोलेरो/बोलेरो कैम्पर** वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे।

मानव–वन्यजीव संघर्ष एवं रेस्क्यू व्यवस्था सुदृढ़ीकरण

उपाय

- वन्यजीवों के कारण मानव मृत्यु होने पर मुआवजा राशि **₹10 लाख** की गई।
- **धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और अलवर** में **रैपिड रिस्पॉन्स टीम** का गठन किया गया।
- वन्यजीव रेस्क्यू हेतु **प्रत्येक जिले को ₹90 लाख** का आवंटन; टीम के लिए **एक वाहन** और आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था।

पर्यावरण विभाग की नीति-सम्बंधी पहल

- राज्य में **सर्कुलर इकॉनोमी नीति** लाई जाएगी।
- **ई-वेस्ट कंडमनेशन नीति** लागू करने की घोषणा।
- प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था मजबूत करने और उद्योगों में **स्व-पालन (सेल्फ कॉम्प्लायंस)** को बढ़ावा देने हेतु **रिवॉर्ड स्कीम** लाई जाएगी।
- जयपुर स्थित राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की **राज्य जल एवं वायु प्रयोगशाला** में **कीटनाशक जांच** के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

RASonly

निष्कर्ष

अनुदान मांगों की स्वीकृति से राजस्थान में अरावली संरक्षण, वृक्षारोपण उपलब्धियों, वन्यजीव सुरक्षा उपकरणों, रेस्क्यू तंत्र तथा पर्यावरण-नीतिगत सुधारों को संस्थागत मजबूती मिलती है। बजटीय प्रावधान, प्रशासनिक क्षमता विस्तार और मापनीय वृक्षारोपण परिणाम—ये सभी बिंदु परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं।

बहुविकल्पीय प्रश्न (आरएएस प्रारम्भिक परीक्षा पैटर्न)

प्रश्न 1. अरावली क्षेत्र से जुड़े वृक्षारोपण और संरक्षण कार्यों के लिए राजस्थान के चालू बजट में कितनी राशि का प्रावधान किया गया है?
(a) ₹90 करोड़
(b) ₹130 करोड़
(c) ₹460 करोड़
(d) ₹202 करोड़
उत्तर: (b)
व्याख्या: चालू बजट में अरावली क्षेत्र में वृक्षारोपण, संरक्षण कार्य और अरावली से निकलने वाले नदी-स्रोत क्षेत्रों के बेहतर रखरखाव के लिए ₹130 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

प्रश्न 2. 'हरियालो राजस्थान' के अंतर्गत पिछले 2 वर्षों में लक्ष्य के मुकाबले कुल कितने पौधे लगाए गए?
(a) 10 करोड़
(b) 7.34 करोड़
(c) 18.54 करोड़
(d) 8.37 करोड़
उत्तर: (c)
व्याख्या: 'हरियालो राजस्थान' में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया था, जबकि समन्वित प्रयासों से 18.54 करोड़ पौधे लगाए गए।

प्रश्न 3. वन्यजीव रेस्क्यू और त्वरित प्रतिक्रिया के लिए रैपिड रिस्पॉन्स टीम किन जिलों में गठित की गई है?
(a) अलवर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर
(b) धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अलवर
(c) कोटा, उदयपुर, सीकर, बाड़मेर
(d) जयपुर, भरतपुर, पाली, चित्तौड़गढ़
उत्तर: (b)
व्याख्या: धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और अलवर में रैपिड रिस्पॉन्स टीम बनाई गई है, जिनके लिए जिला स्तर पर आवंटन और आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था की गई है।

RASonly

Aravalli conservation, afforestation aim, wildlife protection and environment policy announcement in Rajasthan.

The Skill, Planning and Entrepreneurship Minister of Rajasthan Colonel Rajyavardhan Singh Rathore informed the Assembly that the state is going to give a special impetus to the skill training of the youths in border districts. He stated that there will be an attempt to establish a Pokaran Terracotta Skill Center and district-level recommendations will be taken into consideration when training on certain skills. The minister emphasized better coverage: the number of youth trained in 2022 was approximately 60,000, and it was increased to over 100,000 in 2024, and 2026. The other key point noted by him in training is that the current route is through state-level tenders in which the districts are selected by chosen companies and there is a 2026 committee that does research on the skilling gaps and suggests improvement to be made.

Key Announcements

- Skill training at the border districts.
- Attempts at opening the Pokaran Terracotta Skill Center.

- Districts might recommend certain skills, and they will be taken seriously to be trained.

Training Coverage: Essential Numbers.

- 2022-2024: Approximately six hundred thousand young people were trained on skills.
- 2024- 2026: Training coverage grew to 100,000 or over youth.
- 1 Jan 2025 to 31 Dec 2025: the corporation trained 40406 youth in one year.

Existing Training Process and Reform Steps.

Present System

- The skill training is already handled, via state-level tenders.
- Out of the chosen companies determination of the districts to be trained is made.

Reform Initiative (2026)

A committee formed in 2026 will:

- Learn about the skilling gap and propose that training is required.
- Escrigar training-related issues and remedies.
- Think about ways of encouraging skill development in border districts.

Jaisalmer District Overview (Built Environment)

- 2025 (one year): Training provider agencies received a payment of 879204 at Rajasthan Skill and Livelihood Development Corporation, Jaisalmer.

Jan 2020 to Dec 2025: All applications received: total of 12 applications received under:

- DDU-GKY (06), Rajquick (01), Samarth (03), Saksham (01), and CM Nari Shakti Kaushalya Samarthya Yojana (01).

EMD status:

- 11 applications: returned security deposit.
- 1 application: forfeiture of security deposit as a result of non-execution of MoU.

Conclusion

The suggested **Pokaran Terracotta Skill Center** and the particular attention to the border-district skilling are the indications of the attempts to correlate the training with local needs and regional priorities. As training targets increase and the state intends to research the links in the skilling chain, a 2026 committee is to investigate the need

RASonly

to study the gaps within the training and how to remedy the process of bottlenecks to ensure the youth in the border area have access to structured skill development.

MCQs (RAS Prelims Pattern)

Q1. The 2026 committee of Skill, Planning and Entrepreneurship Department was constituted with the main aim of:

(a) Focus on MSP of local crafts and control the pricing of terracotta.

(b) Research gaps in skilling and prescribe training areas including the border districts.

(c) Complete yearly wildlife census in the border states.

(d) Substitute all tenders with direct training recruiting by districts.

Answer: (b)

Explanation: The mandate of the committee is to research the gaps in the skills and recommend areas where skills need to be developed, explore the issues and solutions and think over how the skill acquisition can be encouraged in the border districts.

Q2. What is the figure of training coverage in the Assembly that is correctly matched in each of the following?

(a) 2022–2024: more than 1 lakh; 2024–2026: about 60,000

(b) 2022–2024: about 60,000; 2024–2026: more than 1 lakh

(c) 2022–2024: 40,406; 2024–2026: 18.54 crore

(d) 2022–2024: 7.34 crore; 2024–2026: 8.37 crore

Answer: (b)

Explanation This has been estimated at 2022-2024 with the minister saying that the number had risen to over 100,000 in 2024-2026.

Q3. In Jaisalmer, between 1 January 2025 and 31 December 2025, the corporation trained under the arrangements of the training provider agencies; it trained a total of youth - and paid - to the training provider agencies.

(a) 40,406; ₹8,79,204

(b) 60,000; ₹8,79,204

(c) 40,406; ₹1.30 crore

RASonly

(d) 1,00,000+; ₹90 lakh

Answer: (a)

Explanation: The written response indicated that 40,406 youth were trained within the one year time span and that 879204 was paid to the training provider agencies at Jaisalmer within the one year period.

अरावली संरक्षण, वृक्षारोपण लक्ष्य, वन्यजीव सुरक्षा तथा पर्यावरण-नीति घोषणाएं (राजस्थान)

राजस्थान के कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने विधानसभा को बताया कि राज्य सरकार सीमावर्ती जिलों के युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण को विशेष रूप से बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि पोकरण में **टेराकोटा स्किल सेंटर** स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा तथा जिलों से किसी विशिष्ट कौशल के सुझाव आने पर उस कौशल के प्रशिक्षण पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। मंत्री ने प्रशिक्षण कवरेज बढ़ने का उल्लेख करते हुए बताया कि **2022–2024** के बीच लगभग **60,000** युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया गया, जबकि **2024–2026** में यह संख्या बढ़ाकर **1,00,000 से अधिक** कर दी गई है। उन्होंने यह भी बताया कि वर्तमान व्यवस्था में कौशल प्रशिक्षण के लिए **राज्य स्तरीय टेंडर** जारी होते हैं और चयनित कंपनियां तय करती हैं कि वे किस जिले में प्रशिक्षण देंगी। इस प्रणाली में सुधार के लिए **वर्ष 2026** में एक समिति गठित की गई है, जो कौशल अंतराल का अध्ययन कर सुधारात्मक सुझाव देगी।

प्रमुख घोषणाएं

- सीमावर्ती जिलों में **कौशल प्रशिक्षण को विशेष प्रोत्साहन**।
- **पोकरण टेराकोटा स्किल सेंटर** खोलने के प्रयास।
- जिलों द्वारा सुझाए गए **विशिष्ट कौशल** के प्रशिक्षण प्रस्तावों पर गंभीर विचार।

प्रशिक्षण कवरेज: प्रमुख आंकड़े

- **2022–2024:** लगभग **60,000** युवाओं को कौशल प्रशिक्षण।
- **2024–2026:** कौशल प्रशिक्षण कवरेज बढ़कर **1,00,000 से अधिक**।
- **1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025:** निगम द्वारा **40,406** युवाओं को एक वर्ष में प्रशिक्षण।

वर्तमान प्रशिक्षण प्रक्रिया और सुधार के कदम

वर्तमान व्यवस्था

- कौशल प्रशिक्षण के लिए **राज्य स्तरीय टेंडर** जारी किए जाते हैं।
- चयनित कंपनियां यह तय करती हैं कि वे **किस जिले में प्रशिक्षण** देंगी।

RASonly

सुधार पहल (2026)

- **2026 में गठित समिति** के प्रमुख कार्य:
    - **कौशल अंतराल (स्किलिंग गैप)** का अध्ययन कर यह सुझाव देना कि किन क्षेत्रों/जिलों में प्रशिक्षण की आवश्यकता है।
    - प्रशिक्षण में आने वाली **समस्याओं** और उनके **समाधानों** पर विचार करना।
    - सीमावर्ती (बॉर्डर) जिलों में कौशल विकास को **प्रोत्साहित** करने के उपाय सुझाना।

जैसलमेर जिला: प्रशासनिक विवरण

- **वर्ष 2025 (एक वर्ष):** राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के माध्यम से जैसलमेर में प्रशिक्षण प्रदाता एजेंसियों को **₹8,79,204** का भुगतान।
- **जनवरी 2020 से दिसंबर 2025:** कुल **12 आवेदन** प्राप्त हुए, जिनमें:
    - **डीडीयू-जीकेवाई (06)**, **राजक्विक (01)**, **समर्थ (03)**, **सक्षम (01)**, **मुख्यमंत्री नारी शक्ति कौशल्य सामर्थ्य योजना (01)**
- **अमानत राशि (ईएमडी) स्थिति:**
    - 11 आवेदनों की अमानत राशि **लौटा दी गई**।
    - 1 आवेदन की अमानत राशि **एमओयू नहीं करने** के कारण **जब्त** कर ली गई।

निष्कर्ष

पोकरण में प्रस्तावित **टेराकोटा स्किल सेंटर** और सीमावर्ती जिलों में कौशल प्रशिक्षण पर विशेष फोकस यह संकेत देता है कि राज्य प्रशिक्षण को स्थानीय जरूरतों और क्षेत्रीय प्राथमिकताओं से जोड़ने का प्रयास कर रहा है। बढ़ते प्रशिक्षण लक्ष्यों के साथ **2026 की समिति** कौशल अंतराल और प्रक्रिया संबंधी बाधाओं की पहचान कर सुधारात्मक कदम सुझाएगी, ताकि सीमावर्ती क्षेत्रों के युवाओं तक संरचित कौशल विकास की पहुंच बेहतर हो सके।

बहुविकल्पीय प्रश्न (आरएएस प्रारम्भिक परीक्षा पैटर्न)

प्रश्न 1. कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग में गठित **2026 की समिति** का मुख्य उद्देश्य क्या है?

(a) स्थानीय शिल्पों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना और टेराकोटा की कीमत नियंत्रित करना

(b) कौशल अंतराल का अध्ययन कर प्रशिक्षण की आवश्यकता वाले क्षेत्रों/जिलों (सीमावर्ती जिलों सहित) की सिफारिश करना

(c) सीमावर्ती राज्यों में वार्षिक वन्यजीव जनगणना पूरी करना

(d) सभी टेंडरों को समाप्त कर जिलों द्वारा सीधे प्रशिक्षकों की नियुक्ति करना

उत्तर: (b)

व्याख्या: समिति का दायित्व कौशल अंतराल का अध्ययन करना, प्रशिक्षण की आवश्यकता वाले

RASonly

क्षेत्रों/जिलों की पहचान कर सुझाव देना, प्रशिक्षण में आने वाली समस्याओं और उनके समाधान पर विचार करना तथा सीमावर्ती जिलों में कौशल विकास को प्रोत्साहित करने के उपाय सुझाना है।

प्रश्न 2. विधानसभा में बताए गए कौशल प्रशिक्षण कवरेज के आंकड़ों का सही मिलान कौन-सा है?
(a) 2022–2024: 1 लाख से अधिक; 2024–2026: लगभग 60,000
(b) 2022–2024: लगभग 60,000; 2024–2026: 1 लाख से अधिक
(c) 2022–2024: 40,406; 2024–2026: 18.54 करोड़
(d) 2022–2024: 7.34 करोड़; 2024–2026: 8.37 करोड़
उत्तर: (b)
व्याख्या: मंत्री के अनुसार 2022–2024 के बीच लगभग 60,000 युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया और 2024–2026 में यह संख्या बढ़ाकर 1 लाख से अधिक कर दी गई है।

प्रश्न 3. जैसलमेर में **1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025** के बीच निगम ने कितने युवाओं को प्रशिक्षित किया और प्रशिक्षण प्रदाता एजेंसियों को कितना भुगतान किया गया?
(a) 40,406; ₹8,79,204
(b) 60,000; ₹8,79,204
(c) 40,406; ₹1.30 करोड़
(d) 1,00,000+; ₹90 लाख
उत्तर: (a)
व्याख्या: एक वर्ष की अवधि में निगम द्वारा 40,406 युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया और उसी अवधि में जैसलमेर में प्रशिक्षण प्रदाता एजेंसियों को ₹8,79,204 का भुगतान किया गया।

RASonly

Jaipur to host first BRICS Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) meeting; preparations and protocols on state-level.

The BRICS Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) will have the first meeting in Jaipur. In order to make its running smooth, a review meeting was held at the Secrecy under the chairmanship of Rajasthan Chief secretary, V. Srinivas to discuss the preparedness of the planned programmes which are to be implemented between 4 to 7 March. There were senior officers in the Ministry of Finance (Government of India), Department of Economic Affairs and the Reserve Bank of India.

The Meeting is important to Rajasthan.

- Gives the world a platform to show its administrative potential, development needs, tourism potential, and cultural heritage of Rajasthan.
- Makes Jaipur a platform of top-level global interactions in the sphere of finance and central bank leadership.

Preparations Reviewed

Core Logistics

- Receiving and sending of delegations.
- Hospitality and accommodation.
- Transport planning, such as necessary pilot vehicles, and route clearance.
- Inter-departmental time-bound liaisons between all the concerned departments.

The systems and administration of the city and security constitute the second category.

- High level of security at the venues, hotels, places of visit, along major routes.
- Hygiene, beautification, and maintenance of the major city roads, event locations, and travel routes.

Health and Emergency Support

- 24-hour medical crews, ambulance, and necessary medications.
- Collaboration with the local hospitals to provide the swift response capacity.

Visit to a Heritage and to a cultural programme.

- Plans were discussed to visit and have cultural programme at the Amer Fort.
- The programme is likely to introduce the international delegates to the traditions of folk dance, music, and hospitality of Rajasthan.
- Services such as guides trained, parking management, and necessary facilities of visitors are arranged.

The Outreach and Delegate Support section concerns the idea of the general organization of the entire program in terms of the responsibility of the service representatives who perform the duties on behalf of patients.

- Rajasthan art and handicraft souvenirs are being prepared to the delegates.
- Issue of a tourism booklet
- Nomination and education of liaison officers to organize with the delegations.

Key Officials Present

Senior state officials and central representatives who included Beneficence Secretary Anu P. Mathai, Joint Secretary Amit Singla and Director Prakash Rajpurohit (Department of Economic Affairs), senior officials of tourism sector, home sector, health sector, finance sector, and urban development sector, police intelligence, Jaipur Police Commissionerate, and other departments were among the participants.

RASonly

MCQs (RAS Prelims Pattern)

Q1. Which event to do with BRICS will be hosted in Jaipur?

(a)BRICS Defence Ministers meeting.

(b) BRICS Science and Technology Summit.

(c) BRICS Finance Ministers and Central Banks Governors meeting (FMCBG) First meeting.

(d) BRICS Parliamentary Forum

Answer: (c)

Explanation: Jaipur is the first BRICS FMCBG conference to be held, which includes finance ministers and central bank governors.

Q2. The schedule of the proposed programme that was discussed during the Jaipur BRICS FMCBG meeting is:

(a) 1–3 March

(b) 4–7 March

(c) 10–12 March

(d) 20–23 March

Answer: (b)

Goal: Preparations were checked over the proposed events to be held between 4 and 7 March.

Q3. What was the venue checked in the suggested delegate visit and cultural programme?

(a) Nahargarh Fort

(b) Hawa Mahal

(c) Amer Fort

(d) Jal Mahal

Answer: (c)

Explanation: The visit and cultural programme arrangements a proposed visit and cultural programme to Amer Fort were among the aspects covered by the review such as guides, parking and facilities.

RASonly

जयपुर में ब्रिक्स वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंक गवर्नरों (एफएमसीबीजी) की प्रथम बैठक की मेजबानी; राज्य स्तर पर तैयारियां एवं प्रोटोकॉल व्यवस्था

ब्रिक्स देशों के **वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंक गवर्नरों (एफएमसीबीजी)** की **प्रथम बैठक** जयपुर में आयोजित होगी। आयोजन को सुचारु बनाने के लिए राजस्थान के मुख्य सचिव **वी. श्रीनिवास** की अध्यक्षता में सचिवालय में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें **4 से 7 मार्च** के बीच प्रस्तावित कार्यक्रमों की तैयारियों पर चर्चा की गई। इस बैठक में भारत सरकार के **वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलात विभाग** तथा **भारतीय रिजर्व बैंक** के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

राजस्थान के लिए बैठक का महत्व

- यह आयोजन राजस्थान की **प्रशासनिक क्षमता**, **विकास प्राथमिकताओं**, **पर्यटन क्षमता** और **सांस्कृतिक विरासत** को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का अवसर देता है।
- जयपुर को वित्त एवं केंद्रीय बैंक नेतृत्व से जुड़े **उच्चस्तरीय अंतरराष्ट्रीय संवाद** के प्रमुख मंच के रूप में स्थापित करता है।

तैयारियों की समीक्षा

मुख्य व्यवस्थाएं (लॉजिस्टिक्स)

- प्रतिनिधिमंडलों के **आगमन, स्वागत एवं आवागमन** की व्यवस्था
- **आवास एवं आतिथ्य** प्रबंधन
- परिवहन योजना, आवश्यकतानुसार **पायलट वाहन** तथा **रूट क्लीयरेंस**
- सभी संबंधित विभागों के बीच **समयबद्ध अंतर-विभागीय समन्वय**

सुरक्षा तथा शहर प्रबंधन

- आयोजन स्थल, होटलों, भ्रमण स्थलों और प्रमुख मार्गों पर **कड़ी सुरक्षा व्यवस्था**
- शहर के प्रमुख मार्गों, आयोजन स्थलों और भ्रमण मार्गों की **सफाई, सौंदर्यीकरण और रखरखाव**

स्वास्थ्य एवं आपात सहायता

- **24 घंटे चिकित्सा दल**, एंबुलेंस और आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता
- त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने हेतु **नजदीकी अस्पतालों से समन्वय**

विरासत भ्रमण एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम

- **आमेर किले** में प्रस्तावित भ्रमण एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारियों पर चर्चा हुई।
- कार्यक्रम के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों के समक्ष राजस्थान की **लोकनृत्य, संगीत और आतिथ्य परंपरा** प्रस्तुत करने की योजना है।

RASonly

- **प्रशिक्षित गाइड**, पार्किंग प्रबंधन तथा आगंतुकों के लिए आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था शामिल है।

प्रतिनिधि सहायता एवं संपर्क व्यवस्था

- प्रतिनिधियों के लिए राजस्थान की **कला एवं हस्तशिल्प आधारित स्मृति-चिह्न** तैयार करने की व्यवस्था
- **पर्यटन पुस्तिका** उपलब्ध कराने की योजना
- प्रतिनिधिमंडलों से समन्वय हेतु **लायज़न अधिकारियों की नियुक्ति और प्रशिक्षण**

उपस्थित प्रमुख अधिकारी

बैठक में राज्य के वरिष्ठ अधिकारी तथा केंद्र सरकार के प्रतिनिधि उपस्थित रहे, जिनमें आर्थिक मामलात विभाग की **अतिरिक्त सचिव अनु पी. मथाई**, **संयुक्त सचिव अमित सिंगला** और **निदेशक प्रकाश राजपुरोहित** सहित पर्यटन, गृह, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, वित्त, नगरीय विकास, पुलिस इंटेलिजेंस, जयपुर पुलिस आयुक्तालय तथा अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।

बहुविकल्पीय प्रश्न (आरएएस प्रारम्भिक परीक्षा पैटर्न)

प्रश्न 1. जयपुर में ब्रिक्स से संबंधित कौन-सा आयोजन आयोजित किया जाएगा?
(a) ब्रिक्स रक्षा मंत्रियों की बैठक
(b) ब्रिक्स विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन
(c) ब्रिक्स वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंक गवर्नरों (एफएमसीबीजी) की प्रथम बैठक
(d) ब्रिक्स संसदीय मंच
उत्तर: (c)
व्याख्या: जयपुर में ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की एफएमसीबीजी की प्रथम बैठक आयोजित की जानी है।

प्रश्न 2. जयपुर में प्रस्तावित ब्रिक्स एफएमसीबीजी बैठक के कार्यक्रमों की समीक्षा किस अवधि के लिए की गई?
(a) 1–3 मार्च
(b) 4–7 मार्च
(c) 10–12 मार्च
(d) 20–23 मार्च
उत्तर: (b)
व्याख्या: मुख्य सचिव द्वारा 4 से 7 मार्च के बीच प्रस्तावित कार्यक्रमों—मंत्रिस्तरीय बैठक, प्रतिनिधियों के आगमन, आवास, परिवहन, सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और अन्य व्यवस्थाओं—की समीक्षा की गई।

प्रश्न 3. प्रतिनिधियों के प्रस्तावित भ्रमण एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए किस स्थल की तैयारियों की समीक्षा की गई?
(a) नाहरगढ़ किला
(b) हवा महल

RASonly

(c) आमेर किला
(d) जल महल
उत्तर: (c)
व्याख्या: समीक्षा बैठक में आमेर किले में प्रस्तावित भ्रमण एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारियों—प्रशिक्षित गाइड, पार्किंग व्यवस्था और अन्य आवश्यक सुविधाओं—पर चर्चा की गई।

RASonly